

## RAJYA SABHA

The 5 th September, 1970 the 4th Bhadra.  
(Saka)

The house met at eleven of the clock,  
MR. CHAIRMAN' in the Chair.

### PAPERS LAID ON THE TABLE

#### I. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968-69) OF THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION AND RELATED PAPERS

#### II. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1968) OF THE HYDROCARBONS INDIA PRIVATE LIMITED NEW DELHI AND

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SIR D. R. CHAVAN) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers :—

(i) Ninth Annual Report and Accounts of the Oil and Natural Gas Commission for the year 1968-69, together with the Amendment thereon, under sub-section (3) of section 23 read with sub-section (4) of section 22 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959.

(ii) Fourth Annual Report and Accounts of the Hydrocarbons India Private Limited, New Delhi, for the year 1968, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(iii) Review by Government on the working of the companies mentioned in (i) and (ii) above.

[Placed in Library. See No. LT-41Q3/70 for (i) to (iii)]

#### ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1969) OF AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION BOMBAY, AND RELATED PAPER (HINDI: VII;SI)

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : Sir, I beg to lay on Table, under sub-section (2) of section 32 of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, a copy of the Hindi Version of the Sixth Annual Report and Accounts of the Agricultural Refinance Corporation, Bombay for the year ended the 30th June, 1969, together with the Auditors' Report on the Accounts. [Placed in Library. See No. LT-4161 701]

#### REFERENCE TO FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN BIHAR

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा भारत सरकार का ध्यान बिहार में बाढ़ और अकाल की ओर आकषित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, 1967 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था जो जग विख्यात है और उसके बाद 1970 में अकाल पड़ने जा रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 9½ लाख एकड़ भूमि पर फसल बरबाद हो चुकी है और 36 हजार वर्ग मील का एरिया बाढ़ से एफेक्टेड है और जो बचा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर भी सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। जिन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत वर्षा हुई वह भी सूख रहे हैं। इस तरह से बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति की वजह से अकाल की स्थिति बहुत ही भयंकर हो चुकी है। अगर सरकार इस संबंध में पहले से ही ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है कि वहाँ की जनता को भीषण अकाल का सामना करना पड़े। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह यह न सोचे कि जब विनाश की सीला अपना तांडव नृत्य कर लेगी तब सरकार ध्यान देगी, तो यह वहाँ की जनता के लिए उचित बात नहीं होगी।

केन्द्र की सरकार कहती है कि इस काम की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उसे वह पूरी करे।

[श्री जगदम्बा प्रसाद यादव]

दारी का सवाल है उसके सीमित साधन हैं और वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सकती है।

आज बिहार प्रदेश की यह स्थिति है कि केन्द्रीय सरकार जब तक वहाँ पर अनेक वृहत योजनाएँ शुरू नहीं करती, जब तक वहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की योजनाएँ नहीं होंगी तब तक बराबर बिहार में अकाल पड़ता ही रहेगा और बिहार को अकाल से नहीं बचाया जा सकता है। कोसी की योजना अभी इतने वर्षों से पड़ी हुई है और वह अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। केन्द्र में इससे पूर्व जो सिंचाई मंत्री थे उन्होंने कहा था कि गडक योजना को केन्द्र अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन आज तक यह योजना केन्द्र ने अपने हाथ में नहीं ली है और यही कारण है कि आज तक यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। केन्द्रीय सिंचाई उपमंत्री ने कहा था कि गंगा को बढ़ाकर दक्षिण में कावेरी तक ले जायेंगे, तो मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कम से कम गंगा का पानी का सदुपयोग बिहार में तो हो जाय और दक्षिण बिहार में जहाँ पर पानी की कमी रहती है इसके द्वारा पूर्ति हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि बिहार में भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए वहाँ के वास्ते आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये।

**विपक्ष के नेता (श्री श्यामनन्दन मिश्र) :** चूंकि मैं भी इस मुद्दे से आता हूँ इसलिए वहाँ की स्थिति के बारे में मुझे भी जानकारी है और मैं चाहता हूँ कि उसे सदन के सामने निवेदन कर दूँ। इस समय बिहार की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। सभापति महोदय, जैसा आपको मालूम ही है कि बिहार को इस तरह की स्थिति का सामना पिछले कई सालों में करना पड़ा है और बिहार की आर्थिक अवस्था इसके कारण बहुत खराब हो गई है। वहाँ पर प्रति व्यक्ति की आय देश में सब से ज्यादा कम है। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह की स्थिति के आसार भविष्य में दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि पूर्ण नियोजित ढंग से इसके बारे में कुछ करे। अगर आज से ही हम दृढ़ता के साथ एक योजना के आधार पर काम करेंगे तो वहाँ की स्थिति का मुकाबला करने में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें अगर

माननीय सदस्यों के सहयोग की जरूरत है तो हम सभी इसमें अपेक्षित सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

**श्री भोला प्रसाद (बिहार) :** मैं इस संबंध में पहले भी सरकार का ध्यान दिला चुका हूँ, लेकिन सरकार की ओर से, केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक इस सम्बन्ध में बिहार में जो अकाल पड़ रहा है कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए उसे तीव्र गति से कदम उठाने चाहिये और खाम तौर पर बिहार को अकाल से बचाने के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके लिए कारगर कदम तत्काल उठाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और अभी जिनके बड़े इलाके में यह फसल की बर्बादी हुई है सूखे और बाढ़ के चलते वहाँ लोगों की सहायता पहुँचाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद नहीं की जायगी तो लोगों को जो सहायता पहुँचाई जानी चाहिये वह नहीं पहुँच सकती है और बिहार सरकार उसको करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ जो सिंचाई की योजनाएँ हैं, जिन सिंचाई योजनाओं को लेने की बात की जा रही है उनमें अभी पश्चिमी कोसी नहर का मसाला नेपाल सरकार के साथ उस सम्बन्ध में फैसला नहीं हो जाने के कारण लटका हुआ है। बैसी सूरत में कहा जाता है कि दरभंगा के इलाके में बड़े पैमाने पर स्टेट ट्यूबवेल बैठाए जाएंगे। तो अभी तक जो योजना है वह महज चौबीस पांच-साला योजना के अन्दर अगले साल एक हजार स्टेट ट्यूबवेल बैठाने को पूरे बिहार में है, परन्तु वह बहुत ही नाकाफी है। हमारा ख्याल है कि हंगामा बिहार को जिस तरह अकाल से गुजरना पड़ रहा है प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में सबसे आसानी से और सबसे जल्दी स्टेट ट्यूबवेल के जरिए ही पानी पहुँचाने की गारन्टी की जा सकती है जिससे आगे फसल मारी न जा सके। और भी जो योजनाएँ हैं, जिनके बारे में जिक्र वहाँ किया गया है, चाहे वह गंगा से लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था हो या फिर...

**श्री सभापति :** अब आपने कह लिया, अब आप बन्द करिए।

**श्री भोला प्रसाद :** वह चौबीस-साला में पूरी होनी चाहिए। इसकी गारन्टी केन्द्रीय सरकार की ओर से

जब तक नहीं आती है तब तक बिहार में वह योजना न ली जायगी, न पूरी होगी।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** श्रीमन्, मैं एक इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार को इसके लिए जवाब देने के लिए कहें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। सरकार जवाब देती नहीं है तो बात बढ़ती नहीं है।

#### REFERE CE TO PROGRAMME OF INDEFINITE CEASE-WORK BY TEACHERS OF AFFILIATED COLLEGES OF WEST BENGAL

**SHRI BHUPESH GUPTA** (West Bengal) : Sir seven thousands teachers of the affiliated colleges of West Bengal have taken up a programme of indefinite "Cease work" from the 10th September, because they have failed to get the redressal of their long-standing demands. Sir, (understand that) a delegation of these teachers with the Vice-Chancellor of the Calcutta University is currently in the capital, meeting the Government representatives, Education and other Ministers and I am told they have met even the Prime Minister and the Finance Minister also. Sir, now all I want to point out in this House, since we are coming to the end of this session, is that the Government should give some categorical assurance of financial assistance to them. Their main demand is that all the teachers including those who had come after 1966 should get the benefit of the revised pay. The only thing I want to point out is the indefinite fixation of pay in the new integrated pay scale on notional basis of the third Plan college teachers, new entrants and the teachers of 60-65 age group. This is the important, most important, demand. There are other demands, six or seven demands, enumerated in the document that they placed before the Government. Sir, I think the Government should sympathetically consider—I am glad the Prime Minister is entering the House when I am making a reasonable demand

on behalf of the Calcutta University colleges, affiliated colleges.

Sir, I understand they have met the Prime Minister. Their demand is very very reasonable. They want to get the benefit of the revised scales of pay which is being denied to them, a number of them—well, 7,000 or so are being denied.

Apart from this, there are other demands. It is a matter for the Ministry of Finance to make ad hoc grants or necessary assistance to the University authorities and I think the delegation has been brought here by the representatives of the teachers, headed by the Vice-Chancellor of the University. It should be given due weight and their demands should be accepted and the Government, in the interest of education, should give a categorical assurance that these will be met.

#### REFERENCE TO REBATE ON TEA EXPORTS

**श्री सुन्दर सिंह बंधारी** (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से एक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत वर्ष हमने अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक रिबेट की स्कीम यहाँ पर स्वीकार की थी और जिन वस्तुओं पर रिबेट दिया जा रहा है चाय उन में से एक है। इसका उद्देश्य यह है कि जो फारेन परचेजर हैं उनको यह रिबेट मिले ताकि मार्केट में लोगों को हमारी चाय खरीदने के लिए उत्साह मिले और उसकी मार्केटविलिटी भी बढ़ सके। जो नान-कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उन के लिए तो इस रिबेट का कुछ अर्थ है, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज में जहाँ स्टेट परचेजर हैं, वहाँ पर इस रिबेट का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे यू.एस.एस.आर. कोचीन के मार्केट से एक फर्म नव भारत इंटरप्राइजेज के मार्केट यू.एस.एस.आर. वाले यह चाय खरीदने हैं और वह एक मात्र कंसर्न है इसकी ज़िप्पिंग के लिए भी। पिछले तीन महीनों में ही इस फर्म को इस रिबेट के तौर पर लगभग 8 या 9 लाख रुपया इस दूध्रा है। मुझे यह जानकारी मिली है कि इस इस रिबेट की रकम को प्राप्त करने में इंटरस्टेड नहीं है। तो मैं यह चाहूंगा